श्री नीतीश कुमार: सभापति महोदय, इस तरह के किसी भी प्रस्ताव पर सरकार न विचार कर रही है और न ही इसका इंप्लीमेंटेशन करना किसी के लिए संभव है। यह सुविधा सीनियर सिटीजन को दी जा रही है और अब इसको ऑप्शनल किया जा रहा है। अभी तक हमारा सॉफ्टवेयर ऐसा था, फार्म ऐसा था कि अगर किसी ने अपनी उम्र 65 या उसके अधिक लिख दी तो आटोमेटिकली उसको कंसेशन मिल जाता था। अब उस फार्म में लिखा रहेगा कि क्या आप यह सुविधा लेना चाहते हैं? अगर आप यह सुविधा लेना चाहते हैं तो आपको ट्रैवल के दौरान अपनी ऐज के प्रूफ का कोई न कोई डाक्यूमेंट लेकर चलना होगा। इस प्रकार से जो अमीर लोग हैं, जिनको इसकी जरुरत नहीं है, वे खुद ही इस कंसेशन का लाभ नहीं लेंगे और जो जरुरतमंद लोग हैं। वे इसका लाभ उठाएंगे। पहले ही रेलवे को सीनियर सिटीजन कंसेशन स्कीम के इप्लीमेंटेशन में कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं, दूसरी तरफ उनका क्या इनकम ग्रुप है, वे कितना टैक्स देते हैं, एक बुंकिंग क्लर्क के लिए इन सब बातों का वैरिफिकेशन करना कठिन कार्य है।

PROF. M. SANKARALINGAM: Mr. Chairman, Sir, regarding harrassment being experienced by senior citizens, the hon. Minister replied that they would be required to carry their identity cards while travelling. But that is not possible all the time. Hence, I request the hon. Minister to consider verifying the identity of the person, do the relevant verification at the time of issuing the ticket, rather than at the travelling stage, because they arc all senior citizens and they may forget to carry their identity cards with them while travelling. So, can he think of a new experiment whereby a separate form can be issued and relevant documents as regards their age and identity could be shown to the ticket-issuing clerk at the time of issuing the ticket? Can the Department, under the instruction of the Railway Minister, examine this view and give direction to verify the record at the time of issuing the ticket, rather than at the travelling stage?

श्री नीतीश कुमार: सर, हमने पहले ही कहा है कि जो भी सुझाव यहां आ रहे हैं उन सबको हम एग्जामिन करेंगे ताकि उनकी परेशानी को कम से कम किया जाए।

कृषि क्षेत्र में विकास दर

*83 **श्री राजीव रंजन सिंह** 'ललन ':@

श्री कपिल सिब्बल:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के कृषि क्षेत्र में चार प्रतिशत वार्षिक विकास दर प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा मौजूदा पूंजी-निवेश बड़ाने की आवश्यकता है;

@सभा में यह प्रश्न श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' द्वारा पूछा गया।

(ख) यदि हां, तो सरकार ने सरकारी क्षेत्र से कृषि क्षेत्र में कितना पूंजी-निवेश करने का निर्णय लिया है, और

(ग) इस समय सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत सरकारी क्षेत्र से कृषि में लगाया जा रहा है?

कृषि मंत्री (श्री अजीत सिंह): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1999-2000 को समाप्त दस वर्षों के लिए कृषि सकल घरेलू उत्पाद की औसत मिश्रित वृद्धि दर 3.1 प्रतिशत प्रति वर्ष थी। इसे बढ़ाकर 4 प्रतिशत प्रति वर्ष करने के लिए निजी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र, दोनों द्वारा अतिरिक्त निवेश की जरुरत होगी। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी वर्ष 1999-2000 के राष्ट्रीय आय के त्वरित अनुमानों के अनुसार, सरकारी क्षेत्र से कृषि में संकल निश्चित पूंजी सृजन (जी.एफ.सी.एफ.) 1993-94 के मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद का 0.46 प्रतिशत था। कृषि में सार्वजनिक क्षेत्र के सकल निश्चित पूंजी सृजन में मुख्यतया सिंचाई परियोजनाओं में होने वाला निवेश सम्मिलित है। कृषि में सार्वजनिक निवेश के आबंटन का पता दसवीं योजना को अंतिम रुप दिए जाने के बाद लगेगा। वर्तमान वर्ष के बजट में कृषि विकास के लिए बुनियादी ढ़ांचे को मजबूत बनाने हेतु बड़ी मात्रा में आबंटन किए गए हैं। इनमें कृषि क्षेत्र के लिए ऋण की अतिरिक्त व्यवस्था (10,500 करोड़ रुपये), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण के लिए अतिरिक्त धनराशि (2,500 करोड़ रुपये) तथा ग्रामीण विघुतीकरण के लिए बढ़ा हुआ आबंटन (750 करोड़ रुपये) आदि शामिल हैं। इन सबसे कृषि में निवेश बढ़ाने तथा परिणामस्वरुप कृषि में वृद्धि दर बढ़ाने में मदद मिलेगी।

Growth Rate in Agricultural Sector

† * 83. SHRI RAJIV RANJAN SINGH
"LALAN'® SHRI KAPIL SIBAL:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether there is a need to increase the existing capital investment by Government for achieving four per cent annual growth rate in the agricultural sector in the country;

(b) if so, the extent of capital investment Government have decided to make from the Government sector in agricultural sector; and

† Original notice of the question was received in Hindi.
@ The question was actually asked on the floor of the House by Shri Rajiv Ranjan Singh "Lalan".

(c) the percentage of gross domestic product being invested presently in the agricultural sector from the Government sector?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI AJIT SINGH): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

The ten year Average Compound Growth Rate of agricultural Gross Domestic Product (GDP) ending 1999-2000 was 3.1 % per annum. To increase it to 4% per annum, additional investment both by private sector and Government sector would be needed. According to the Quick Estimates of National Income for the year 1999-2000 released by the Central Statistical Organisation, the Gross Fixed Capital Formation (GFCF) in Agriculture from Government sector was 0.46% of the Gross Domestic Product, at 1993-94 prices. The GFCF of public sector in agriculture mainly consists of investment in irrigation projects. Allocation of public investment in agriculture will be known after the finalisation of the Tenth Plan. During the current year's budget substantial allocations have been provided for strengthening the infrastructure for the development of agriculture. These include additional flows of credit to agricultural sector (Rs. 10,500 crore), additional funds for construction of roads under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (Rs. 2,500 crore) and enhanced allocations for rural electrification (Rs. 750crore), etc. All these will help in enhancing the investment in agriculture and consequently increase the rate of growth of agriculture.

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन ': सभापति महोदय, सरकार की जो घोषित कृषि नीति है उसके अनुसार चार प्रतिशत वार्षिक उत्पादन दर में वृद्धि की चर्चा है और इसके लिए जो अभी पूंजी निवेश हो रहे हैं उसमें लगभग उससे दोगुने पुंजी निवेश की आवश्यकता होगी। लेकिन सरकार के उत्तर में है कि पूंजी निवेश की राशि का पता टेंथ प्लान के बाद ही चल पाएगा। तो मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि (ए)-सरकार के पास जो प्रस्तावित पूंजी निवेश है उसमें सरकारी क्षेत्र से और निजी क्षेत्र से कितने-कितने पूंजी निवेश का प्रस्ताव है? (बी)-जो राशि प्रस्तावित है उस राशि में मूलभूत सुविधा के लिए कितनी है, जो नई टेक्नोलाजी है, नई मशीनरी है उसके लिए उपयोग में आने वाली कितनी राशि का प्रस्ताव है? जो रनिंग इंवेस्टमेंट है उस रनिंग इंवेस्टमेंट के लिए क्या प्रस्ताव है और अंत में फसल के बाद जो 10 से 40 प्रतिशत की हानि होती है, उत्पादन के बाद उसको मीट करने के लिए उसमें क्या प्रस्ताव है?

श्री अजीत सिंह: जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि टेंथ प्लान तैयार हो जाएगा तभी यह पता चल सकता है कि कितनी पूंजी किस क्षेत्र में लगेगी । लेकिन यह एक एस्टीमेट लगाया गया है कि

1999-2000 में करीब बीस हजार करोड़ रुपया केपिटल फार्मेशन था और 2006-2007 में करीब 30 हजार करोड़ रुपए की जरुरत पड़ेगी 3.1 से 4 परसेंट कृषि दर को बनाने के लिए। लेकिन यह पूंजी निवेश किस क्षेत्र में होगा और कहां से होगा, पब्लिक सैक्टर में, प्राईवेट सैक्टर में उसका कितना होगा, जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि जब टेंथ प्लान तैयार हो जाएगा तभी यह बताया जा सकेगा।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': महोदय, सरकार ने कृषि के बढ़ाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात अपने उत्तर में की है उसमें सड़क की चर्चा है, बिजली की चर्चा है और क्रेडिट फ्लों की चर्चा है। लेकिन कृषि को बढ़ाने के लिए जो सबसे मेजर कम्पोनेंट है- सिंचाई उसके इंवेस्टमेंट की चर्चा इसमें नहीं है। तो मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सिंचाई के क्षेत्र में भी इस पर व्यय करने का विचार है?

श्री अजीत सिंह: जब ग्रौस केपिटल फार्मेशन की हम बात कर रहे हैं तो यह बेसिकली सिंचाई में ही हैं। सड़क, रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन, गोडाउन यह सब इसमें इंक्लूड नहीं हैं और असल में एक कमेटी अभी मिनिस्ट्री ने बनाई है रियलिस्टिक पिक्चर देने के लिए कि क्या-क्या चीजें इस केपिटल फार्मेशन में इंक्लूड होनी चाहिए। अब जो इनके फिगर्स आपको दिए हैं वह सिर्फ बेसिकली इरिगेशन के बारे में ही हैं। तो जितना पैसा लग रहा है, जितना प्लान है वह ज्यादातर सिंचाई में ही लग रहा है।

SHRI KAPIL SIBAL : Mr. Chairman, Sir, the Minister should be aware of the fact that from 1993 to 1999, public investment in agriculture has declined from 32 per cent to 24 per cent. Even in GDP terms, it has declined from 1.6 per cent to 1.1 per cent. In the private sector also, there has been a continual decline from 1993. As per the results of the first quarter of the year 2000-2001, the investment is barely 0.2 per cent. Now, in this situation, when the private sector industrial growth is also down to 1.9 per cent, you cannot expect the private sector to investment in agriculture; and when the public investment has gone down, where are you going to get the money from the invest in the public sector to achieve a 4 per cent growth? It is all » very well for you to say that you are going to wait for the 10th Plan statistics and figures. Where are you going to get the money from, and how do you believe that you will raise this money, when it is already on the decline? Could you please answer that? Part (b) of my supplementary is this. Are you considering making irrigation part of the infrastructure so that the maximum investment goes into that area?

SHRI AJIT SINGH : Sir, the hon. Member is right in saying that the investment in agriculture has been going down. In fact, not only these figures, if you look at the figures from the 50's to 2000, you will find that the share of investment in agriculture has gone down to about eight per cent; from

20 per cent to eight per cent. But, at the same time, the share of agriculture, in GDP terms, has gone down from 58 per cent to about 25 per cent. So, if you look at the share of investment in agriculture, as a percentage of GDP, it has remained static; at slightly less than 0.5 per cent. The growth in the industry and the service sector has been-faster, as they are capital intensive also. Therefore, the investment in these sectors is more. The overall investment, as far as GDP goes, remains the same. But the hon. Member's concern is right. We should all be concerned about it, because while the share, in GDP terms has gone down, the number of people involved is still the same. That is affecting the living standard of the people who are dependent on agriculture.

SHRI KAPIL SIBAL: In fact, unemployment in the rural sector has increased. There is no further investment. You cannot absorb these people anywhere else. So something really drastic has to be done. Your Agriculture Policy should show us the way, but, unfortunately, nothing has been happening at the ground level.

SHRI AJIT SINGH: Sir, in this years Budget, more than Rs. 10,000 crores of additional money has been given for rural credit प्रधान मंत्री जी की जो सड़क योजना है उसके लिए साढ़े सात हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं। रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए भी साढ़े सात सौ करोड़ रुपये इस साल के बजट में हैं। यह समस्या रिर्सोसेज की है। अगर हमको चार परसेंट बढ़ाना है तो इसके लिए रिर्सोसेज ढूंढ़ने पड़ेंगे। इसीलिए टेंथ प्लान के बारे में जो डिसकशन चल रहा है उसमें ये सवाल उठाये जा रहे हैं।

श्री कपिल सिब्बल: अभी सरकार क्या कर रही है?

श्री अजीत सिंह: सभपति महोदय, मैंने अभी बताया है कि यह बजट में दिया गया है कि बढ़ाये गये हैं।

प्रो. रामगोपाल यादव: सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि आजादी के तत्काल बाद से अब तक देश के सकल घरेलू उत्पाद में जो खेती का हिस्सा था वह लगभग 50 फीसदी रहा है और अब यह घटकर लगभग 24 फीसदी के आसपास रह गया है। आज खेती बिल्कुल घाटे का सौदा रह गया है। इससे किसान निराश और हताश हैं। केवल सरकार इन्वेस्टमेंट करे, पैसा दे और बढ़ाये उससे काम नहीं चल सकता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि किसानों को उनकी उपज का लाभप्रद मूल्य नहीं मिल रहा है उसे दिलाने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? जब तक किसान मन लगाकर खेती नहीं करेगा, यह मानकर नहीं चलेगा कि उसे कुछ लाभ हो सकता है तब तक आप चाहे जितना पैसा उसे दीजिए खेत में काम करने वाले हाथ जब तक निराश और दुखी होंगे तब तक उत्पादन नहीं बढ़ सकता है, शेयर नहीं बढ़ सकता है। किसान का

मनोबल बढ़ाने के लिए क्या आप इस बात की जांच करवायेंगे कि प्रति हैक्टेयर गेहूं पैदा करने में कितनी लागत आती है और आप उसको कितना देने जा रहे हैं, किसान गन्ना पैदा करता है उसमें कितनी लागत आती है और आप उसे कितना देने जा रहे हैं, किसान धान पैदा करता है उसमें कितनी लागत आ रही है और आप उसे कितना दे रहे हैं? अगर वह लाभ का नहीं है तो इससे कुछ काम चलने वाला नहीं है। इसलिए किसान को लाभकारी मूल्य देने के लिए आप क्या योजना बना रहे हैं?

श्री अजीत सिंह: माननीय सदस्य ने वही चिंता व्यक्त की है कि जी.डी.पी. में ऐग्रीकल्चर का शेयर कम हो रहा है और हरेक डैवलपिंग इकॉनामी में यह जरुरी भी है कि वह शेयर कम हो लेकिन साथ ही जितने लोग कृषि में लगे हुए हैं, उनकी संख्या भी कम होनी चाहिए ।

प्रो. रामगोपाल यादव: किन्तु वह जैसी की तैसी है ।

श्री अजीत सिंह: जी हां, वह जैसी की तैसी है। जैसा मैंने कहा कि सबसे बड़ी समस्या यही है। जहां तक मूल्यों की आप बात कर रहे हैं, दाम देने की बात है। सी.ए.सी.पी. है, कमीशन ऑन ऐग्रीकल्चर प्राईसिज है। यह सब चीजें ही वह कंसीडर करती है जो आप कह रहे हैं इसके अलावा इसी सरकार की बात नहीं है, पिछले 6-7 सालों में सरकारों ने वह दाम बढ़ाने की कोशिश की है और बढ़ाए भी गये हैं। गेहूं का देख लीजिए, चावल का देख लीजिए, पल्सिज का देख लीजिए लेकिन समस्या यही आ रही है और किसान इसलिए परेशान है क्योंकि उसकी जोत कम होती जा रही है। पर अगर आप यह कहें कि किसान के दाम नहीं बढ़े हैं या उसको लाभ के दाम नहीं मिल रहे हैं तो ऐसा नहीं है लेकिन पहले जहां उसके पास 10 एकड़ की खेती थी, अब 70 से 80 प्रतिशत लोगों के पास एक हैक्टेयर से कम खेती हो गयी है। जब तक हम कृषि में लगे हुए लोगों को दूसरी तरफ नहीं भेजेंगे, जब तक आप उघोग लगाने का काम नहीं करेंगे, शेयर कम होता जाएगा। जैसा मैंने कहा कि हरेक डैवलपिंग कंट्री में यह जरुरी है। अमेरिका में आज सिर्फ एक परसेंट लोग खेती पर निर्भर रह गये हैं। जब तक इतने ही लोग खेती में लगे रहेंगे, तो वे परेशान होते रहेंगे, यह लाज़िमी है। इसलिए हमें उघोगों को बढ़ावा देने की जरुरत है।

प्रो. रामगोपाल यादव: सर, इस पर एक डिबेट होनी चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है, उस पर डिबेट होनी चाहिए कि गवर्नमेंट क्या करे। आज भी इस पर जो लोड है और आजादी के इतने वर्षों के बाद आज भी 75-76 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हैं, उनको कैसे दूसरी तरफ भेजा जाए?

श्री सी०एम० इब्राहीम: सर इस पर हाफ एन ऑवर डिसकशन फिक्स कर दीजिए। काफी लोगों की यह मांग है कि इस पर हाफ एन ऑवर डिसकशन करवाइए।

श्री सभापति: आधा घंटा तो अभी हो भी गया है।

श्री नागेन्द्र नाथ ओझा: सभापति महोदय, विकास का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उस चार परसेंट विकास दर को हासिल करने के लिए क्या इसमें इस बात का आकलन किया गया है कि यह कृषि के क्षेत्र में कितने प्रतिशत रोजगार को सृजित करेगा और खासतौर से महिलाओं के मामले में-जो महिलाएं कृषि पर निर्भर हैं, जो वहां मजदूरी करती हैं और जो दूसरे कार्यों में नहीं जा सकती, जो सिर्फ कृषि पर निर्भर हैं, वेज अर्नर्स के रुप में हैं, उनके रोजगार के अवसर घटे हैं। तो विकास का जो भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है, क्या उसके केन्द्र बिन्दु में रोजगार के अवसर को बढ़ाना है? अगर यह केन्द्र बिन्दु में नहीं है तो क्या इसको केन्द्र बिन्दु मानकर विकास के लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे?

श्री अजीत सिंह: महोदय, बेरोजगारी की समस्या केवल कृषि के क्षेत्र में ही नहीं, वरन हरेक क्षेत्र में बढ़ रही है। अब अगर इंडस्ट्री को भी बढ़ाते हैं, कितना ही रेट बढ़ाएं, तो उसमें भी यह सोचने की जरुरत है। यह सही बात है कि सब से ज्यादा रोजगार कृषि के क्षेत्र में आज भी हैं और अगर कृषि का रेट चार परसेंट बढ़ेगा तो मेरा मानना है कि उसमें रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे लेकिन उसको केन्द्र बिन्दु बनाकर कि रोजगार कैसे बढ़ाया जाए, इससे ज्यादा हमें इम्प्रूव्ड टैक्नीक्स पर ज्यादा ध्यान देने की जरुरत है। नये इरीगेशन के तरीके हैं, नये सीड्स हैं, बायो टैक्नोलॉजी है, जो रेन फैड एरिया हैं, उसमें कैसे बढ़ा सकते हैं, जो हमारे देश में कमी है। किस तरह से ऐग्रीकल्चर को डायवर्सीफाई किया जाए जिससे ग्रोथ रेट बढ़ सके। इसको केन्द्र बिन्दु रखकर योजनाएं बनाई जा रही हैं और मेरा विश्वास है कि अगर रेट बढ़ेगा तो इसमें से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

SHRI S. RAMACHANDRAN PILLAI: Sir, the overall situation in agriculture in distressing. The investment in agriculture is declining and the growth and the compound growth of agricultural production is also declining. If you compare the pre-refprm period with the postreform period from 1981 to 1992, the average rate of growth was 3.9%. It declined to 3.26% during 1993—2000, if you look at the annual compound rate of growth during the period 1981—92, it was 3.4% and during the period 1993—2000, it was 2.2%. It is public investment that attracted more private investment and it is public investment that can find a solution to the problem ot" uneven growth. In the present situation, would the Government consider making more public investment in agriculture?

SHRI AJIT SINGH: The rate of growth earlier was, basically, due to the reason that we were concerned about food security. The whole emphasis was on rice, wheat and other such things. Now that we have achieved food security, our emphasis for growth is more on flowers, seeds, fruits and that kind of things. You are right in that, more investment is needed and better

needed. We are all concerned about increasing the investment in agriculture because, in the last one or two years, it has gone down. Whatever may be the political party and whatever may be their thinking, leftist or rightist, everybody is concerned because agriculture is still, and is likely to continue to be the backbone of our economy. So, we have to increase the investment.

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERSTO STARRED QUESTIONS

Study of Law in Secondary Education

*84. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government are considering a proposal to include Law as a subject in the Secondary Education;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefore?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) to (c) The National Council of Educational Research & Training (NCERT) has prepared a Curriculum Framework at the national level. Decision regarding inclusion of a subject for study for school is taken by the Central Board of Secondary Education (CBSE) and the States' School Boards in the light of NCERTs Curriculum Framework. There is no reference in the NCERTs National Curriculum Framework to the inclusion of law as a subject at the secondary level. CBSE also does not have any proposal to introduce law as a subject at the secondary level.

Pollution in India

* 85. SHRI P. PRABHAKAR REDDY: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news report appearing in the Telegraph, dated 28th May, 2001 under the caption ""India on pollution black list";

(b) if so, Government's reaction thereto; and

(c) the steps proposed to be taken to address the problems raised in the